arrangements for audits of the accounts of the Schemes at all levels. The Ministry has, accordingly, in consultation with the CAG, notified on 30th June, 2011, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Audit of Schemes Rules, 2011. All States have been asked to put in place a robust Social Audit Mechanism as out lined in these Rules.

——————————

12.00 NOON

SHORT NOTICE QUESTION

Fund distribution as per population and area

1. SHRI NARESH CHANDRA AGRAWAL: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the norms for allocation of funds to the schemes being run by Central Government for the development of villages;

(b) whether it is a fact that a big State like Uttar Pradesh is not getting the full benefit of these schemes, considering its huge population and area;

(c) if so, whether Government would lay down the norms relating to these schemes on the basis of area and population; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI JAIRAM RAMESH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The Ministry of Rural Development is implementing through State Governments and UT Administrations various rural development programmes namely; Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), Swarnjayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY)/National Rural Livelihood Mission (NRLM), Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), Indira Awas Yojana (IAY) and Integrated Watershed Management Programmes (IWMP). Besides, the other rural development programmes namely National Rural Drinking Water Programme (NRDWP) and Total Sanitation Campaign are now being implemented by the Ministry of Drinking Water and Sanitation

The Central allocation to the States including Uttar Pradesh is based on predetermined criteria of the Planning Commission as per the objectives of the respective rural development programmes. The area and population of the States are not the only parameters for Central allocation. The allocation based schemes of the Ministry of Rural Development are SGSY/NRLM, IAY and NRDWP and other schemes *i.e.* MGNREGA, IWMP and TSC are demand/project

based. Central allocation to the States including Uttar Pradesh under SGSY, IAY and NRDWP is given as below:—

SGSY: Central allocation under SGSY is made amongst the States on the basis of 'Adjusted shares' worked out by the Planning Commission based on the 1993-94 poverty ratios.

IAY: Funds are allocated among the States/UTs giving 75% weightage to rural housing shortages as per 2001 Census and 25% weightage to poverty ratio.

NRDWP: Funds are allocated to States on the criteria of rural population-40% weightage, rural SC/ST population 10%, areas under Desert Development Programme, Drought prone Areas Programme, Hill Area Development Programme, Special Category Hill States-40% and population managing their own water supply schemes-10%.

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी प्रश्न संख्या 283 के जवाब में कह रहे थे...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप इस पर सवाल पूछिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: सर, मैं इस पर ही सवाल पूछ रहा हूं कि दक्षिण भारत, उत्तर भारत और नार्थ ईस्ट तीनों की स्थिति अलग-अलग है। मैंने भी इस संदर्भ में प्रश्न किया है और मेरा मूल प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी उत्तर भारत की विशेष परिस्थिति को देखते हुए जो भी ग्रामीण योजनाएं हैं, उनका मानक क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर रखेंगे या नहीं? माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि कुछ योजनाओं को छोड़कर बाकी को नहीं रखेंगे, क्योंकि ये मानक योजना आयोग ने बनाए हैं, मंत्री जी के विभाग ने नहीं बनाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके आधार पर केवल पॉपुलेशन और एरियाज़ को नहीं लिया जा सकता।

माननीय मंत्री जी, मैं आप से सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की योजनाओं के लिए आपने जिन मानकों को रखा है और इतने वर्षों से इन मानकों से जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का क्या रिज़ल्ट आया? इसके साथ ही आगे कितने वर्षों में उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के सारे गांव इन योजनाओं से saturate हो जाएंगे? मैं इसके साथ यह भी पूछना चाहता हूं...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: केवल एक सवाल।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: सर, इसी से जुड़ा हुआ है।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: हर चीज़ दुनिया में जुड़ी हुई है। आप केवल एक ही सवाल पूछिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: माननीय सभापति जी, जब हम और आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो सभी कुछ जुड़ गया।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: हम सब देश से जुड़े हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: जब सर्वोच्च पीठ उत्तर प्रदेश से जुड़ गई तो फिर सभी कुछ जुड़ ही गया। माननीय मंत्री जी, मैं उत्तर प्रदेश का विशेष उल्लेख करते हुए, आप से यह पूछना चाहता हूं कि आप जो

मनरेगा की 100 days की बात कर रहे हैं, आपने इस 100 days पर जो रुपया खर्च किया है, इससे आप रोजगार देने की बात करते हैं, तो आप लोगों को 100 days के बजाए 365 दिन काम दीजिए। आप *मनरेगा* पर प्रति वर्ष 40,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, उससे अब तक क्या एसेट्स तैयार हुए हैं?

श्री जयराम रमेश: सर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि हम जो मानक बनाते हैं, ये योजना आयोग के मानक हैं। इनके आधार पर ही हमारा मंत्रालय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को धनराशि आबंटित करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में इस साल करीब 88,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस 88,000 करोड़ रुपए में से मात्र 14 फीसदी BPL या गरीबों के आधार पर है, क्योंकि ये ऐसे कार्यक्रम हैं, जो मांग के आधार पर हैं। *मनरेगा* कार्यक्रम मांग के आधार पर है, PMGSY कार्यक्रम मांग के आधार पर है। जैसे कि *इंदिरा आवास योजना* है या गरीबों और बुजुर्गों के लिए *पेंशन की योजना* है या *पेयजल योजना* है, वहां गरीबी और आबादी दो मानक जरूर होते हैं। आप जानते हैं कि वित्त आयोग और योजना आयोग के माध्यम से राज्यों को धनराशि मिलती है और जो मानक लगाए जाते हैं, उनमें से करीब 60 प्रतिशत आबादी का होता है। करीब 15 से 20 प्रतिशत तक परकैपिटा इन्कम का होता है। मैं नहीं समझता कि किसी राज्य के साथ भेदभाव हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आपने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो *मनरेगा* का जिक्र किया है, इस साल करीब 20 फीसदी आबंटन उत्तर प्रदेश को गया है। हालांकि आबादी के आधार पर उत्तर प्रदेश का हिस्सा 16 प्रतिशत है, लेकिन उसकी तुलना में 20 प्रतिशत पैसा उत्तर प्रदेश को गया है।

मान्यवर, ये जो मानक हैं, ये ज्यादातर आबादी के आधार पर हैं। हमारा मंत्रालय इनमें कोई दखल नहीं देता है। यह पैसा वित्त आयोग और योजना आयोग के आधार पर दिया जाता है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के स्तर पर आने के लिए और कितने साल लगेंगे, तो मैं कहता हूं कि यह सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार पर निर्भर है।...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: मान्यवर, नहीं...(**व्यवधान**)...

श्री वीर सिंह: सर,...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बैठ जाइए, बैठ जाइए।

श्री जयराम रमेश: अभी धनराशि की कोई कमी नहीं है।...(**व्यवधान**)... अगर इसको ढंग से खर्च करेंगे...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बैठ जाइए।...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश: अगले दस साल में उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य हो सकता है।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: थैंक यू, दूसरा सवाल पूछिए।...(**व्यवधान**)... बैठ जाइए। अग्रवाल जी, आप दूसरा सवाल पूछिए।...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: माननीय मंत्री जी, आपके तमाम मंत्री, जो इस सरकार के मंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वे उत्तर प्रदेश जाकर लगातार यह बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र के पैसे का सही उपयोग नहीं कर रही है। आपके कुँवर साहब भी यही बयान देते हैं। वे अभी उत्तर प्रदेश गए थे, उन्होंने भी यही बयान दिया।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: प्लीज़, आप सवाल पूछिए, भाषण मत दीजिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: श्रीमन्, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। इस देश में सबसे ज्यादा प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश के हुए और वे भी कांग्रेस के थे। सबसे ज्यादा उपेक्षा उत्तर प्रदेश की हुई। सबसे ज्यादा साल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार रही, उपेक्षा हुई। हमारी सरकार को तो चार ही साल हुए हैं। माननीय मंत्री जी, आप जानना चाहते हैं, आपकी जो IAY है...(**व्यवधान**)... मैं क्वैश्चन पर आ रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, we have other business to transact. If this debate goes on, how we will close discussion on the question.

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: मैं क्वैश्चन पूछ रहा हूँ।

माननीय मंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में दो चीज़ें लाना चाहता हूँ और उनका उत्तर भी चाहता हूँ। आप IAY ले लीजिए। IAY में उत्तर प्रदेश में BPL का 2002 तक का जो सर्वे था, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब 22 लाख परिवार बिना मकान के रह जाएँगे और उसको पूरा करने में करीब 8-10 साल लग जाएँगे। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में 200 की आबादी तक की घोषणा हुई थी। अभी भी उत्तर प्रदेश में 500 तक की आबादी का फंड पूरा release नहीं हुआ, जिससे 500 तक की आबादी के गाँव सड़क से जुड़ जाएँ। 200 की आबादी वाले तो पूरी तरह से छूट गए। यह उपेक्षा किसकी तरफ से हो रही है? माननीय मंत्री जी, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चूँकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने जा रहे हैं, कब आचार संहिता लग जाए, उत्तर प्रदेश का विशेष ध्यान रखते हुए क्या आप उत्तर प्रदेश के लिए योजना आयोग से निवेदन करेंगे? माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं। माननीय वित्त मंत्री जी हम लोगों का अनुरोध सुन लें। क्या आप योजना आयोग से अनुरोध करेंगे कि वह अपने मापदंडों को बदलते हुए, वे राज्य, जो बहुत पिछड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश सहित और भी उत्तर भारत, जहाँ देश की आबादी के 50 प्रतिशत लोग रहते हैं, उनके लिए विशेष मानक बनाते हुए उनको विशेष फंड देंगे? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जयराम रमेश: सर, वास्तविकता यह है कि योजना आयोग के तहत विशेष मापदंड होते हैं और पिछड़े राज्यों के लिए एक special treatment दिया जाता है। योजना आयोग से बुंदेलखंड पैके ज की घोषणा हो चुकी है। कई ऐसे कार्यक्रम हैं, जिनमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, उत्तर-पूर्वी राज्य हैं, उनके लिए स्पेशल दर्जा दिया गया है।

सर, इन्होंने कई बात उठाई है। एक तो इन्होंने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में ज़िक्र किया। मैं आपको बिना राजनीति के उत्तर देना चाहता हूँ, हालांकि आप इसको बार-बार एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का यह मकसद था कि जो 500 से ऊपर की आबादी है, 500 plus habitation है, उसको जोड़ा जाए। धन राशि की कमी थी। इसलिए हमने उन आबादियों को प्राथमिकता दी, जिनकी पॉपुलेशन 1000 से भी ऊपर थी। आपको यह जान कर खुशी होगी कि कल ही हमने निर्णय लिया है कि हम इस सीमा को अभी और कम करें और 800 से लेकर 999 तक जो habitations हैं, हम उनके लिए भी सारे भारत में PMGSY में काम करेंगे।...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: 500 तक की घोषणा हो चुकी है।

श्री जयराम रमेश: आप मेरी पूरी बात तो सुनिए।...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: आप 800 से 1000 ले रहे हैं। हम 500 से 200 पर जा रहें हैं और आप 800 से 1000 पर जा रहे हैं!

श्री जयराम रमेश: एक तो आप बिल्कुल गलतफहमी में हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में कभी नहीं कहा गया था कि 200 की आबादी ली जाएगी। यह कभी नहीं कहा गया था।...(**व्यवधान**)... मुझे मेरी बात खत्म तो करने दीजिए। पहले चरण में हम 800 से लेकर 999 तक की आबादी लेंगे। जब वहाँ के 90 प्रतिशत works sanction होंगे, काम sanction होंगे, तब हम 600 से लेकर 799 तक की आबादी लेंगे। हम यह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माँगें बहुत आ रही हैं। अभी आपने केरल से सुना कि हमें upgradation के लिए पैसा चाहिए। कई दक्षिण भारतीय राज्यों से और माँगें आ रही हैं। हम PMGSY में जो पैसा खर्च करते हैं, इस साल हमने करीब 20 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं, अगर हमारे पास अनगिनत पैसा होता, तो हम लोग 10 या 15 की आबादी भी लेते। लेकिन, क्योंकि धनराशि की कमी है और तीस राज्यों में हमें इसे बाँटना है, इसीलिए हम इसे चरणों में ले रहे हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि कल ही हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 800 से लेकर 999 तक की आबादी को इससे जोड़ा जाएगा।

आपने पहले कहा कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तर प्रदेश को कोई मंजूरी नहीं दी गई है।...(**व्यवधान**)... प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 26 जिलों में करीब 500 सड़कों के लिए हमारे पास प्रस्ताव आया था, हमने उसको तुरंत मंजूरी दी है। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश का कोई भी प्रस्ताव प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमारे मंत्रालय में रुका हुआ है, यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है।...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: श्रीमन्,...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आपको दूसरा सवाल पूछना है या तकरीर करनी है?...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: सर, मैं जो पूछ रहा हूँ, उसका जवाब ही नहीं आया।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: अगर आपको जवाब नहीं मिला है, तो आप लिखित में दीजिए कि सवाल का जवाब unsatisfactory था।...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: माननीय सभापति जी, अगर हम नये सदस्यों को आपका संरक्षण नहीं मिलेगा तो हम लोगों का बड़ा नुकसान होगा।...(**व्यवधान**)... हम सीखने के लिए आए हैं।...(**व्यवधान**)... कुछ सीखने के लिए आए हैं।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please don't waste time. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: हम प्रयास कर रहे हैं कि अपनी बात को कह सकें।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप अपना दूसरा सवाल पूछ लीजिए। दूसरे लोगों को भी सवाल पूछने हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: जी, सर...(**व्यवधान**)... माननीय मंत्री जी,...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: सर, ये दोनों सवाल पूछ चुके हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: दोनों पूछ चुके?...(**व्यवधान**)... O.K. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: मैंने एक ही पूछा है, सर।...(**व्यवधान**)... माननीय सभापति जी, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आपने सवाल पूछ लिए हैं।...(**व्यवधान**)... Sorry ...(**व्यवधान**)... नहीं, अब आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... अब आप बैठ जाइए।...(**व्यवधान**)... श्री मोहन सिंह।

श्री मोहन सिंह: सभापति महोदय, अभी योजना आयोग के उपाध्यक्ष बुंदेलखंड गए थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को बुंदेलखंड के विकास के लिए जो विशेष फंड दिया, उत्तर प्रदेश के हिस्से में उसका सदुपयोग नहीं हुआ और अभी तक पूरा खर्च नहीं हुआ। मनरेगा में उत्तर प्रदेश में जो गड़बड़ियाँ थीं, माननीय मंत्री जी ने खुद ही उनके सम्बन्ध में अनेक सार्वजनिक बयान दिये, पत्र लिखे और सी.बी.आई, से जाँच कराने की माँग की।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिन राज्यों को आप केन्द्रीय फंड से पैसा देते हैं और यदि उस फंड का दुरुपयोग होता है, उसकी ठीक से समीक्षा नहीं होती, तो क्या केन्द्र से इसकी जाँच की कोई विशेष व्यवस्था सी.ए.जी. के जरिए या अपनी ही तरफ से सी.बी.आई. के जरिए इसकी जाँच कराने की कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री जयराम रमेश: हमारे पास तीन विकल्प हैं। पहला है - पैसा रोकना, जिसके पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। दूसरा है - सी.बी.आई. की जाँच। सी.बी.आई. की जाँच तभी हो सकती है, जब हम लोगों को राज्य सरकार की सहमति हो और वह कभी होती नहीं है, तो CBI enquiry भी नहीं हो सकती है।...(**व्यवधान**)... जो तीसरा विकल्प है या तीसरा रास्ता जो हमने अपनाया है, वह सी.ए.जी. का ऑडिट है। आपको जानकर खुशी होगी कि पहली बार सारे ग्रामीण विकास कार्यक्रम — इसमें कुछ शंका थी, कुछ doubts थे कि क्या सी.ए.सी. ऑडिट लागू हो सकता है, परन्तु सी.ए.जी. की मुलाकात के बाद हमने यह निर्णय लिया है कि सारे ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सारे 28 हजार करोड़ रुपए, जो इस साल खर्च होंगे, सी.ए.जी. ऑडिट की perview में आएँगे और इसकी शुरुआत हम मनरेगा से करेंगे। सी.ए.जी. परफॉर्मेंस ऑडिट 12 राज्यों में करेगी और अलग-अलग महत्वपूर्ण राज्यों के लिए स्पेशल ए.जी. भी नियुक्त किए जाएँगे। तो सी.ए.जी. ही हमारे पास एकमात्र रास्ता है. जिससे हम कुछ नियंत्रण रख सकते हैं। परन्तु, यह बात सही है कि मैंने मुख्य मंत्री जी को खत लिखा था कि 7 ऐसे जिले हैं, जहाँ भारी मात्रा में घोटाले उभर कर निकले हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री ब्रजेश पाठक: वह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित था।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए।...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: उनको अपनी बात पहले खत्म करने दीजिए।...(**व्यवधान**)...

श्री ब्रजेश पाठक: अगर इनको जाँच करानी थी तो उत्तर प्रदेश सरकार...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: यह आपका सवाल तो नहीं है?...(**व्यवधान**)...

श्री ब्रजेश पाठक: जहाँ भी भ्रष्टाचार की बात आती है, हमारी सरकार उससे सख्ती से...(**व्यवधान**)... और वह उसकी जाँच कराती है।...(**व्यवधान**)... इस तरह से राजनीतिक बयानबाजी करना उचित नहीं है। ...(**व्यवधान**)... मैं उस बयान की भर्त्सना करता हूँ...(**व्यवधान**)... मैं उसकी निंदा करता हूँ ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए।...(**व्यवधान**)...

श्री ब्रजेश पाठक: चुनाव के समय इस तरीके से आपको काम नहीं करना चाहिए।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: The Short Notice Question is over.